**उपसभापति** : अगर टेलीफोन पर किसी ने नाम बताया होता तो आप प्रिविलेज दे सकते थे । लेकिन वह बेनामी आया है।

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया** : यह बात नहीं है.....

SHRI V. GOPALSAMY: Didn't have the courage to tell his name to Mr, Ahluwalia.

**उपसभापति** : आप तो सब लोगों के राइट्स के प्रोटेक्टर हैं, आप को क्या प्रोटेक्शन ?

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया** : राइट्स जिनके हाथ में हैं, वे उसका मिसन्यूज कर रहे हैं ।

**उपसभापति** : देखिये, मैं तो आपको प्रोटेक्शन दे रही हूं, आपको हाउस में बोलने दे रही हूं ।

## LOSS OF FOREST AND WILDLIFE DUE TO CONSTRUCTION OF HOUSES BY TERRORISTS GROUPS IN DUDHWA AND CORBETT NATIONAL PARKS IN UTTAR PRADESH

**डा० संजय सिंह** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, पिछले सप्ताह नेशनल जौगरफिक मैगजिन के कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर मेरे पास थे । उनकी इच्छा थी नेशनल कार्बेट पार्क जाने की । मैंने व्यक्तिगत तौर पर उत्तर प्रदेश के वन विभाग के कुछ अधिकारियों से पार्क जाने की इच्छा जाहिर की । महोदया, उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नेशनल कार्बेट पार्क एकदम अनसेफ है, वहां पर टैरोरिस्टों के हाइड-आउट्स हैं । यहां तक कि वन विभाग के अधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वे बिना तीन-चार आदमियों बिना हथियारों के नेशनल कार्बेट पार्क में प्रवेश न करें । वहां पर पुलिस और नेशनल कार्बेट पार्क के जो अधिकारी हैं, मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना कि.....

**श्रीमती कमला सिन्हा** (बिहार) : गृह मंत्री जी व्यस्त हैं ।

**डा० संजय सिंह** : मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नेशनल कार्बेट पार्क...

SHRI KAMLA SINHA: The Home Minister should pay attention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Home Minister is now paying attention. So please don't disturb him.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY. AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I didn't go away from my seat.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I wanted to convey that you are paying attention as you have put on the headphone.

**डा० संजय सिंह** : जब नेशनल कार्बेट पार्क के लिए सीधा मन हो गया तो मैंने सोचा जो नेशनल दुधवा पार्क खीरी-लखीमपुर जिले में है, वहां पर जाया जाय । वहां के अधिकारियों से जब संपर्क स्थापित किया गया तो उन्होंने भी टोटल अनसेफ का एलान किया और कहा कि वहां भी जाना उचित नहीं है । इस रिपोर्ट के बाद हमें इस बारे में कुछ जानकारी हुई तो और भी ज्यादा इच्छा हुई कि इस बारे में विस्तृत जानकारी मालूम की जाय । जानकारी में महोदया, यह पता चला कि दिसम्बर में जो टूरिस्ट के लिए पीक सीजन होता है, वहां कोई भी टूरिस्ट नहीं गया और यहां तक रिपोर्ट मिली है कि दिन में और रात में आंतकवादियों का नाम लेकर वहां पर बहुत ही ज्यादा अवैधानिक रूप से जंगलों की कटाई हो रही है । इसी तरह से अवैधानिक तरीके से अन्य जन्तुओं का शिकार का एक तरह से अभियान चल रहा है । वहां पर प्रदेश सरकार से जब इस बारे में बात की जाती है कि वहां पर मंदिर और मस्जिद के अलावा और कोई इश्यू ही नहीं है और दिल्ली में जब बात की जाती है तो उनको यह सूट करता है कि ला एंड

[डा० संजय सिंह]

आर्डर प्रदेश सरकार का सबजैक्ट है । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जिलों में टैरोरिस्टों का आतंक भयावह तरीके से है । शाम 6 बजे के बाद किसी भी थाने में ताले नहीं खुले होते, सारे पुलिस कर्मी अंदर होते हैं । जब कोई वहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है तो अंदर से एलान हो जाता है कि सुबह 8 बजे आकर मिलो ।

वहां पर यह जो भयावह स्थिति देखने को मिलती है, उसका मेरा अपना जाती अनुभव भी है । मैंने दो तीन दिन से यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जिससे सिर्फ यह मालूम हुआ कि सरकार के कोई बड़े अधिकारी के जाने का इंतजाम है, न पुलिस वहां जाती है और न कोई पर्यटक वहां जाता है । ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी वहां चोरी हो रही है, बहुत सारी पोचिंग हो रही है जानवरों की । मैं यह चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, प्रदेश सरकार के कोआर्डिनेशन के साथ वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे शांति व्यवस्था कायम हो और वन्य प्राणियों की रक्षा हो तथा करोड़ों रुपयों की जो वन्य सम्पदा की चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिए भी कोई व्यवस्था हो सके । मैं चाहूंगा कि ला एंड आर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, यह कह कर इस प्रश्न को टाला नहीं जाना चाहिए बल्कि एक कम्प्रेहेंसिव अरेंजमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि वहां पर जो भय व्याप्त है जिसके कारण वहां वनों के अधिकारी और कर्मचारी भी नहीं जाते हैं, बाहर से देखने वाला कोई जाना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में कोई फोरमल सी बात न हो बल्कि पक्की व्यवस्था हो । धन्यवाद ।

**Need to convert Shahgang-Mhow Rail-Way line Into broad gauge line.**

**श्री राम नरेश यादव** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय सब से पहले तो मैं डा० संजय सिंह ने जो तराई क्षेत्र में बढ़ते हुए आतंकवाद की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उसके साथ अपने आपको एस्सोसिएट करना चाहता हूं । (व्यवधान) महोदया, प्रदेश की सरकार इस समस्या को हल करने में विफल साबित हुई है, हो गई है, इसलिए, केन्द्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए । प्रदेश सरकार ने तो सत्ता में बने रहने का अधिकार ही खो दिया है ।

उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसे इस सदन में सन् 1988 से लेकर अब तक कई बार उठाया गया और सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया, वह प्रश्न है पूर्वांचल में आजमगढ, मऊ और उधर गाजीपुर, बलिया के विकास का प्रश्न । इस विकास का संबंध जुड़ा हुआ है छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने से, वह भी शाहगंज से मऊ तक । महोदया, पहले मऊ आजमगढ़ जनपद में था लेकिन दो भाग में विभाजित हो जाने से मऊ दूसरा जिला बन गया और आजमगढ़ जिला अलग से रह गया, आजमगढ़, जनपद और इन दोनों के बीच से मऊ भी जंक्शन है और जंक्शन जुड़ता है । इस स्थिति में 1908 से जो छोटी लाइन चली आ रही है, उसकी स्थिति बहुत विचित्र है । इस रेलवे लाइन के किनारे करीब 20 ऐसे कस्बे हैं जहां पर प्रदेश के बहुत से मशहूर बुनकर रहते हैं और यह बुनकर किसी तरह से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं । वहां की बुनी हुई साड़ियां बनारस में आ कर बनारसी साडी के नाम से जानी जाती हैं और एक्सपोर्ट भी की जाती हैं जिससे सरकार को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । लेकिन इसके बवजूद भी सरकार ने आज तक बहुत दिनों से चली आ रही डिमांड की ओर ध्यान नहीं दिया । साथ ही साथ कम से कम तीन ऐसे अरेबिक और फारसी के इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर करीब-करीब सभी अरब देशों के छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं । दूसरी ओर तीर्थ स्थल भी हैं । लेकिन यह सारा इलाका गरीबी से दबा हुआ रहता है । वहां के लोग रोजी-रोटी की तलाश में